विवरण–IV

बाह्य सहायतित आवासीय परियोजनाएं

परियोजना का नाम	1992–93 के लिये बजट अनुमान	92–93 के लिये संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये में)	92–93 में हुआ व्यय	अध्युक्ति
1. के.एफ.डब्ल्यू. हुडको–II (ऋण)	34.00	34.00	23.45	अब तक प्राप्त बाह्य सहायता हुडको को पूर्ण रूप से संवितरित कर दी गई है। यदि 31–3–93 तक आगे कोई संवितरण प्राप्त नहीं होता है तो व्यय न की गई शेष राशि जमा कर दी जायेगी।
2. के.ई.डब्ल्यू (ऋण)	8.0	15.00	7.03	–वही–
3. के.एफ.डब्ल्यू.हुडको–III (भवन निर्मिति अनुदान)	5.00	5.00	के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा कोई संवितरण नहीं किया गया है।	के.एफ.डब्ल्यू. से और अनुदान प्राप्त होने पर ही इस वर्ष के प्रावधान को उपयोग में लाया जा सकता है।
4. ओ.ई.सी.एफ.हुडको (ऋण)	45.00	6.00	ओ.ई.सी.एफ द्वारा कोई संवितरण नहीं किया गया है।	ओ.ई.सी.एफ.से ऋण प्राप्त होने पर इस वर्ष के प्रावधान को उपयोग में लाया जा सकता है।

गुजरात में जन सुविधाओं के लिये धन राशि का आवंटन

633. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा गत तीन ... के दौरान गुजरात को राज्य में जन-सुविधाओं में सुधार हेतु कुल कितना धन आवंटित किया गया और इस कार्य के लिए कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) राज्य की जन सुविधाओं से संबंधित कितनी योजनाएं केंद्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं और इस संबंध में

स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) :

(क) सिर पर मैला ढोने वालों की इस कुप्रथा से मुक्ति के लिए कम लागत के स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता दी जाती है तथा गुजरात सरकार ने सहायता हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Amendment in Delhi Rent Control Act

634. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to reply to Unstarred Question 1939 given in the Rajya Sabha on the 4th December, 1992 and state:

(a) whether the amendments proposed to be made in the Delhi Rent Control Act, have since been finalised;

(b) if so, what are the details, and if not, what are the reasons therefor; and

(c) when the proposed legislation is likely to be brought before Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) The proposal to amend the Delhi Rent Control Act on the lines of the Model Rent Control Legislation has since been finalised and the Bill is likely to be introduced in the Parliament during this year.

Number of People Living in Slums in Delhi

635. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the estimated number of people living in slums in Delhi and what is their percentage to the total population of Delhi;

(b) what efforts have been made by Government to provide them the basic amenities; and

(c) whether Government propose to spend a minimum amount per person for this purpose and, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) According to Municipal Corporation of Delhi, the squatter population comprises about 929 jhuggi jhonpri clusters mostly on public land and having about 13 lakh persons in January, 1990. These figures are on the basis of a survey conducted by the Government of National Capital Territory of Delhi in January, 1990. In relation to the Census population of 1991, the squatter population is 13.8 per cent of total population.

(b) and (c). According to MCD, the approved plan scheme of Environmental Improvement in J.J. Clusters along with related scheme of Jan Suvidha Complexes for J.J. Dwellers are under implementation by the slum and J.J Department of MCD. Under this scheme, basic civic amenities as